आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 25.07.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किए।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों से चयन वर्ष 2025–26 के तहत पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों की सूचना 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने को कहा।
- महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

उपराष्ट्रपति चुनाव

निवार्चन आयोग ने कानून और न्याय मंत्री के परामर्श से राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिये सहायक चुनाव अधिकारी बनाया है। संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिदेश प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विनियम, 1974 से संचालित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है।

मुख्यमंत्री बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जहां भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य हो, वहां शीघ्र मरम्मत की जाए और पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले स्कूल भवनों की कार्ययोजना बनाकर तत्परता से क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब स्थिति वाले पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाए और कहीं भी जर्जर पुलों के कारण कोई जनहानि न हो। मुख्यमंत्री ने त्रियुगीनारायण और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जा रहे राज्य के अन्य स्थलों की कार्यवाही में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने इन स्थलों के विकास में गुणवत्ता, सुविधा और सांस्कृतिक गरिमा का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दो आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाने की दिशा में भी तेजी से कार्य करने की बात कही।

मुख्यमंत्री शुभाकामनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लम्बा कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

हरियाली तीज

राजभवन में आज हरियाली तीज, पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजभवन में कार्यरत महिला अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की पत्नियों ने भाग लिया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रथम महिला गुरमीत कौर ने सभी महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दीं और उनके जीवन में सुख–समृद्धि की कामना की। उन्होंने हरियाली तीज को भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा, नारी शक्ति की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में भी मदद मिलती है।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को चयन वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों का आकलन पहली जुलाई तक की स्थिति के अनुसार करते हुए, संबंधित सूचना अनिवार्य रूप से 15 अगस्त तक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए यह जरूरी है कि सभी विभाग समय पर आकलन कर निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं भेजें, ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियत समय पर आयोजित की जा सके। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पदों पर पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं या अन्य कारणों से पदोन्नति नहीं की जा सकी है, उनके संबंध में उचित कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

श्रीदेव सुमन

टिहरी राजशाही के खिलाफ 84 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए टिहरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में श्रीदेव सुमन को याद किया गया। आज टिहरी कारागार आम जनता के लिए खुला रहा और राजशाही के दौरान उन पर पहनाई गई हथकड़ियां और बेड़ियां आम लोगों के दर्शनार्थ रखी गईं। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और विधायक किशोर उपाध्याय ने जिला कारागार में श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रीदेव सुमन के जीवन से प्रेरणा लेकर सभी को उनके पद्चिन्हों पर चलना चाहिए।

स्टॉन्ग रूम सुरक्षा

बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सभी मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज़ से प्रशासन ने सीसीटीवी, डबल गार्ड ड्यूटी और पुलिस बल की तैनाती जैसी कड़ी व्यवस्थाएं की हैं।

चमोली बैठक

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में विभागीय परिसंपत्तियों की डिजिटल पॉलीगन– सीमांकन कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार पॉलीगन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्र परिसंपत्तियों का चिन्हीकरण व सीमांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग की परिसंपत्तियों की सीमाओं को चिन्हित कर निर्धारित पोर्टल पर समय से अपलोड करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के तहत विभागीय परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए यह कार्य बहुत जरूरी है। इस दौरान उन्होंने जिला स्तर पर पोर्टल में डेटा अपलोड करने में आ रही समस्याओं का समाधान करने के ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर

को निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को पॉलिगन कार्य की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और उप जिलाधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए।

अश्लील ओटीटी बंद

केंद्र सरकार ने अश्लील और अशालीन सामग्री दिखाने वाले 25 ओटीटी वेबसाइट और एप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है।

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में 25 वेबसाइटों को भारत में सार्वजनिक पहुंच से वंचित करें।